संख्या-100 /2023/आई0/670/23-9-2023/001-23-9002(002)/13/2022

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-9** **लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2023**

**विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0 एफ0-28 योजनान्तर्गत जनपद कानपुर नगर में झांसी-कानपुर रेल मार्ग पर सम्पार सं0-240ए , दादा नगर के पास प्रस्तावित दूसरे 02 लेन समानान्तर रेल उपरिगामी सेतु परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पत्र सं-रा0बैं0उ0प्र0क्षे0का0/284/राज्य परियोजना विभाग/आर0आई0डी0एफ0-04/RIDF-XXVIII/2022-23, दिनांक 09.03.2023 एवं मुख्य अभियंता(सेतु), लो0नि0वि0 के निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-28 योजनान्तर्गत जनपद कानपुर नगर में 01 रेल उपरिगामी सेतु परियोजना, कुल लागत रू0 53,77,00,000/- (रूपये तिरपन करोड़ सतहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापे रू0 11,70,43,000/- (रूपये ग्यारह करोड़ सत्तर लाख तिरालीस हजार मात्र) (जिसमें अनुदान संख्या-57 के लेखाशीर्षक 5054-04-101-36-00-24 से 78.79 प्रतिशत धनराशि रू0 922.18 लाख एवं अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 5054-04-789-21-00-24 से 21.21 प्रतिशत धनराशि रू0 248.25 लाख देय होगा), की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| क्र. | कार्यालय प्रमुख अभियंता(सेतु विंग), लो0नि0वि का पत्र | जनपद | कार्य का नाम | राज्यांश(सेतु निगम अंश की लागत, यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं भूमि अध्याप्ति की लागत) | रेलवे अंश की लागत | कुल लागत | वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | अनुदान सं0-57 | अनुदान सं0-83 | योग (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 11/आर0ओ0बी0/कानपुर क्षेत्र/बी0एम0सी0/2022, दि0 08.04.2022 | कानपुर नगर | जनपद कानपुर नगर में झांसी-कानपुर रेल मार्ग पर सम्पार सं0-240ए , दादा नगर के पास प्रस्तावित दूसरे 02 लेन समानान्तर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य। | 4681.71 | 695.29 | 5377.00 | 922.18 | 248.25 | 1170.43 |

**(1) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।**

**(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनु02 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(9) प्रायोजना में यदि भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तो भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमोंके अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(10) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(11) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा लगाई गई शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा नाबार्ड शर्तों एवं योजना की गाइड लाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) विभाग द्वारा वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 एवं यथा संशोधित शासनादेश सं0-23/2022/ बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक- 04 नवम्बर, 2022 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(16) प्रश्नगत कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग में सम्पादित कराये जा रहे कार्यो हेतु Third Party Quality Audit/Inspection प्रणाली एवं रोड सेफ्टी आडिट प्रणाली, विकसित करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1850/23-12-17, दिनांक 22.11.2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(17) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(18) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(19) मार्ग सुरक्षा के प्राविधान आई0आर0सी0 कोड के अनुसार किये जाये।

(20) प्रस्तावित रेल उपरिगामी सेतु रेलवे विभाग द्वारा रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित एवं निर्माण लागत में सहभागिता सुनिश्चित होने के पश्चात निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

(21) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष का होगा।**

**(22) विभाग द्वारा बड़े शहर जहां जनसंख्या प्रसार की संभावना बहुत अधिक है वहां पर दो लेन रेल उपरिगामी सेतु के स्थान पर जहां तक संभव हो सके 04 लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण से संबंधित प्रायोजनाओं में आर0ओ0डब्ल्यू0 की उपलब्धता के दृष्टिगत यूटीलिटी शिफ्टिंग इस प्रकार की जाय कि भविष्य में चार लेन/छः लेन निर्माण किये जाने पर पुनः इन्हें किये जाने की आवश्यकता न हो।**

**(23) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। आर0ओ0बी0 निर्माण की जी0ए0डी, लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, आर0ई0वाल एबेटमेंट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।**

**(24) प्रायोजना में यूटीलिटी शिफ्टिंग हेतु विद्युत विभाग, नगर निगम, सेंट्रल यू0पी0 गैस लि0(सी0यू0जी0एल0), बीएसएनएल, वन विभाग एवं जल निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आगणन के सापेक्ष क्रमशः रू0 10.49 लाख, रू0 38.51 लाख, रू0 50.00 लाख, रू0 50.00 लाख, रू0 0.33 लाख एवं रू0 1011.28 लाख अनुमन्य की गयी है। विभाग द्वारा उक्त कार्य मदों पर संबंधित विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति के उपरांत कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।**

**(25) प्रश्नगत रेल उपरिगामी सेतु (रेलवे पोर्शन के कार्य को छोड़कर) के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 होगी।**

**2- इस संबंध में होने वाला व्यय ( *1* ) रुपये 9,22,18,000 ( रुपये नौ करोड़ बाईस लाख अठारह हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041013600 प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य ( *2* ) रुपये 2,48,25,000 ( रुपये दो करोड़ अड़तालीस लाख पच्चीस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047892100 नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माणमानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

**3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-767-X-2022-23, दिनांक- 19-3-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीय
शिव कुमार
अनु सचिव।

**<u>संख्या उपरोक्त तददिनांक</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
9- महाप्रबंधक रेलवे, संबंधित जोन द्वारा मुख्य अभियंता(सेतु) लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
12- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
13- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
15- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।

आज्ञा से,

शिव कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।